नईदुनिया

जर्मनी में इंसानों के लिए खतरा बने भेड़ियों को देखते ही गोली मारने के आदेश

बर्लिन

जर्मनी में पिछले तीन दशकों से संरक्षित भेड़ियों की बढ़ती आबादी अब इंसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। इस समस्या से निपटने के लिए जर्मनी के निचले सदन (बुंडेस्टाग) ने एक ऐतिहासिक और कड़ा कानून पारित किया है, जिसके तहत अब भेड़ियों का शिकार करना कानूनी रूप से मान्य होगा। यह फैसला उन हजारों किसानों और ग्रामीणों के पक्ष में लिया गया है जो लंबे समय से इन शिकारी जानवरों के आतंक से जूझ रहे थे। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए इस बिल को विपक्षी दलों का भी व्यापक समर्थन मिला है, जो दर्शाता है कि अब वन्यजीव संरक्षण और ग्रामीण सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य हो गया है।

आंकड़ों के अनुसार, अकेले वर्ष 2024 में भेड़ियों ने लगभग 4,300 पालतू जानवरों, जिनमें मुख्य रूप से भेड़, बकरियां और बछड़े शामिल थे, को अपना निवाला बनाया। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेताओं ने इस कानून की वकालत करते हुए कहा कि भेड़ियों की बढ़ती संख्या ने पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगाड़ दिया है और बेगुनाह मवेशियों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। नए कानून के तहत जर्मनी के सभी 16 राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे जुलाई से अक्टूबर के बीच उन क्षेत्रों में शिकार की अनुमति दे सकें जहां भेड़ियों का घनत्व बहुत अधिक है। विशेष रूप से उन भेड़ियों को किसी भी मौसम में मारने की अनुमति होगी जिन्होंने पहले कभी पालतू जानवरों पर हमला किया है। इस नीतिगत बदलाव के पीछे एक बेहद चर्चित व्यक्तिगत घटना भी जुड़ी हुई है। साल 2022 में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन के प्रिय पालतू टट्टू डाली को हनोवर के पास एक भेड़िये ने मार दिया था। इस हाई-प्रोफाइल घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भेड़ियों के कंजर्वेशन स्टेटस की समीक्षा की मांग तेज हो गई। आखिरकार यूरोपीय संघ ने भी अपनी सुरक्षा रेटिंग में ढील दी, जिससे जर्मनी जैसे देशों के लिए शिकार को वैध बनाने का रास्ता साफ हो गया। इसे एक बड़े कूटनीतिक और नीतिगत बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है जिसने दशकों पुराने संरक्षण नियमों को बदल दिया है। हालांकि, इस कानून को लेकर जर्मनी के भीतर विरोध के स्वर भी तेज हैं।

न्यूज ब्रीफ

ईरान में अमेरिकी-इजराइली हमले में मारे गए खामेनेई के बेटे मोजतबा को चुना गया सर्वोच्च नेता

तेहरान। अमेरिका-इजराइल के सैन्य अभियान में 28 फरवरी को मारे गए ईरान की इस्लामिक क्रांति के लीडर और सर्वोच्च नेता दिवंगत अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे अयातुल्ला सैयद मोजतबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी चुन लिया गया। मोजतबा इस्लामिक क्रांति के लीडर और देश के सर्वोच्च नेता होंगे। 88 सदस्यीय एक्सपर्ट्स असेंबली (मजलिस-ए-खोबरेंगान-ए-रहरी) ने मोजतबा का देश के सर्वोच्च नेता के रूप में चुनाव किया। एक्सपर्ट्स असेंबली को ईरान की सबसे ताकतवर धार्मिक विशेषज्ञ सभा भी कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की एक्सपर्ट्स असेंबली ने अयातुल्ला सैयद मोजतबा खामेनेई को इस्लामिक क्रांति का नया लीडर चुना। असेंबली ने कहा कि मोजतबा के पिता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने 1989 में इमाम खुमैनी की मौत के बाद 37 साल तक ईरान का नेतृत्व किया। उनकी शहादत के बाद असेंबली ने मोजतबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी चुन लिया। असेंबली ने रविवार देररात जारी बयान में इस घोषणा के साथ 28 फरवरी के हमले में इमाम खामेनेई और अन्य दूसरों की शहादत पर दुख जताया। ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले की निंदा की। बयान में कहा गया है कि इमाम खामेनेई की शहादत के तुरंत बाद और युद्ध के हालात व दुश्मनों की सीधी धमकियों के बावजूद असेंबली ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और नए नेता को चुनने की प्रक्रिया शुरू की।

जब ईरान से अलग होकर बना था कुर्दों का स्वतंत्र देश, छोटा लेकिन प्रभावशाली

तेहरान। 1946 में ईरान के उत्तर-पश्चिमी शहर महाबाद में कुर्दों ने अपने स्वतंत्र राज्य, महाबाद गणराज्य या कुर्दिस्तान गणराज्य की स्थापना की थी। 22 जनवरी 1946 को कुर्द नेता काजी मुहम्मद ने इस गणराज्य की घोषणा की। काजी मुहम्मद लंबे समय से कुर्दों के सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे और स्वतंत्र कुर्द राज्य आंदोलन के प्रमुख चेहरे बन चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलते भू-राजनीतिक हालात ने कुर्द आंदोलन को अवसर दिया। उस समय उत्तरी ईरान में सोवियत संघ की मौजूदगी थी, जिसका समर्थन कुर्द विद्रोहियों को मिला इस समर्थन से कुर्दों ने महाबाद और आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया और स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी। महाबाद गणराज्य में महाबाद, बुकान, पिरानशहर, उर्मिया और सलमास जैसे कुर्द बहुल क्षेत्र शामिल थे। इस छोटे राज्य ने सांस्कृतिक और सामाजिक सुधारों की शुरुआत की। कुर्द भाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिला, साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला और महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया। गणराज्य की सैन्य शक्ति पेशमर्गा सेना थी। हालांकि, यह स्वतंत्रता लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी।

कई पर्यटन स्थलों के नाम में छिपी है सच्ची कहानियां

तुर्कमेनिस्तान। दुनिया में कई पर्यटन स्थल ऐसे भी हैं जिनके नाम ही लोगों के दिल में दहशत भर देने के लिए काफी हैं। नरक का द्वार, भूतों का शहर और मौत की घाटी जैसे नाम सिर्फ रोमांच बढ़ाने के लिए नहीं रखे गए, बल्कि इन जगहों के पीछे ऐसे कुदरती हादसे, ऐतिहासिक घटनाएं और मानवीय गलतियां जुड़ी हैं। इन नामों के पीछे छिपे किस्से न केवल चौंकाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि प्रकृति और इतिहास किस तरह किसी जगह की पहचान को बदल सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में स्थित दरवाजा गैस क्रेटर को नरक का द्वार कहा जाता है। रेत के बीचों-बीच फैला यह विशाल जलता हुआ गड्ढा पिछले लगभग 50 वर्षों से लगातार आग उगल रहा है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई, जब सोवियत वैज्ञानिक प्राकृतिक गैस की खोज के दौरान गलती से जमीन के भीतर मौजूद एक बड़े गैस भंडार को ध्वस्त कर बैठे। गैस के अनियंत्रित रूप से निकलने के खतरे को देखते हुए इंजीनियरों ने इसमें आग लगा दी, यह सोचकर कि गैस कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। लेकिन गैस का भंडार इतना विशाल था कि आग आज तक नहीं बुझी है। रात के समय इसका दृश्य किसी जलते हुए दरवाजे या पाताल की आग जैसा प्रतीत होता है।

अमेरिका-दक्षिण कोरिया का फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास शुरू, बढ़ सकता है तनाव

सियोल

मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच कोरियाई प्रायद्वीप में भी तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। यूएस और साउथ कोरिया ने सोमवार से संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्डशुरू कर दिया है। यह बड़ा सैन्य अभ्यास 19 मार्च तक चलेगा, जिसमें हजारों सैनिक और कई सैन्य इकाइयां शामिल होंगी। दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ्स आफ स्टाफ के अनुसार इस अभ्यास में लगभग 18 हजार दक्षिण कोरियाई सैनिक भाग ले रहे हैं। वहीं अमेरिकी सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया है। यह अभ्यास मुख्य रूप से कमांड पोस्ट और कंप्यूटर सिमुलेशन पर आधारित होता है, जिसके जरिए बदलते युद्ध परिदृश्यों और संयुक्त सैन्य रणनीतियों का परीक्षण किया जाता है।

इस संयुक्त अभ्यास के बीच दक्षिण कोरियाई मीडिया में यह चर्चा भी तेज है कि वाशिंगटन कुछ सैन्य संसाधनों को दक्षिण कोरिया से हटाकर मध्य-पूर्व क्षेत्र में तैनात कर रहा है। रिपोर्टों में कहा गया है कि कुछ अमेरिकी पैट्रियट एंटी-मिसाइल सिस्टम और अन्य सैन्य उपकरणों को संभावित रूप से ईरान के खिलाफ अभियान के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि अमेरिकी सेना ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन दावों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने भी इन रिपोर्टों पर सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे दोनों देशों की संयुक्त रक्षा रणनीति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा।दूसरी ओर नोर्थ कोरिया लगातार इस तरह के सैन्य अभ्यासों का विरोध करता रहा है। उत्तर कोरिया का कहना है कि ये अभ्यास उसके खिलाफ संभावित हमले की तैयारी का हिस्सा हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने हाल ही में प्योंगयांग में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान सियोल के प्रति कड़ा रुख दोहराया था, हालांकि उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं की।

विश्लेषकों के अनुसार दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। 2019 में ट्रंप और किम जोंग उन के बीच हुई शिखर वार्ता विफल होने के बाद उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ अधिकांश वार्ताएं बंद कर दी थीं। इसके बाद से प्योंगयांग ने अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेज कर दिया है।

भारत-चीन को प्रतिद्वंद्वी नहीं साझेदार बनना चाहिए: वांग यी

बीजिंग। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत और चीन के संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि दोनों देशों को एक-दूसरे को प्रतिद्वंद्वी के बजाय साझेदार और खतरे के बजाय अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि एशिया के विकास और वैश्विक संतुलन के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग और विश्वास बेहद जरूरी है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सैन्य गतिरोध के कारण दोनों देशों के संबंध लगभग पांच वर्षों तक तनावपूर्ण रहे। हालांकि हाल की उच्च स्तरीय बैठकों के बाद संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। दोनों देशों ने वीजा और उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने सहित कई कदम उठाए हैं, जिससे आपसी संबंधों में धीरे-धीरे सुधार देखा जा रहा है। बीजिंग में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा तय किए गए मार्ग पर चलकर ही दोनों देशों के संबंधों को स्थिर और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। वांग यी ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई बैठकों ने रिश्तों को सुधारने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अगस्त में तियानजिन में मोदी और शी जिनपिंग की सफल मुलाकात हुई थी। इसके साथ ही वर्ष 2024 में कजान में हुई उनकी बैठक से शुरू हुई सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाते हुए तियानजिन शिखर सम्मेलन ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती दी है। वांग ने कहा कि इन बैठकों के बाद सभी स्तरों पर संवाद फिर से सक्रिय हुआ है और द्विपक्षीय व्यापार ने नया रिकार्ड भी बनाया है। साथ ही लोगों के बीच संपर्क और आदान-प्रदान भी बढ़ा है, जिससे दोनों देशों की जनता को ठोस लाभ मिल रहा है। वांग यी ने कहा कि भारत और चीन को भविष्य के संबंधों को लेकर सही रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अच्छे पड़ोसी की तरह संबंध बनाए रखना चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त रूप से काम करना चाहिए। उनके अनुसार, विकास और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना दोनों देशों के हित में है।

ट्रम्प की ऑस्ट्रेलिया से अपीलः ईरानी महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा दें

तेल अवीव/तेहरान, एजेंसीः अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का दसवां दिन है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑस्ट्रेलिया से अपील की है कि वह ईरान की महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को शरण दें। ट्रम्प ने चेताया कि अगर खिलाड़ियों को ईरान वापस भेजा गया तो उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है और यह मानवीय दृष्टि से बड़ी गलती होगी। यह मामला ऑस्ट्रेलिया में चल रहे महिला एशियन कप के दौरान सामने आया। 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद महिला टीम ने राष्ट्रगान नहीं गाया, जिसे ईरानी सरकार ने देशद्रोह के रूप में देखा। ट्रम्प ने कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया आश्रय देने के लिए तैयार नहीं है, तो अमेरिका खिलाड़ियों को सुरक्षा देगा। इसके साथ ही इजराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के अल-अंसारिया गांव के निवासियों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। सेना ने कहा कि हिज्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है और निवासियों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है।

इजराइल ने दावा किया कि उसकी वायुसेना ने ईरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के ड्रोन हेडक्वार्टर पर हमला किया। इस अभियान में ड्रोन स्टोरेज और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। इजराइल का उद्देश्य ईरान की ड्रोन हमले की क्षमता को कमजोर करना है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि उनका देश ईरान के हमले झेल रहे देशों की रक्षा करेगा। इसके लिए फ्रांस पूर्वी भूमध्यसागर और लाल सागर में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है। मैक्रों ने स्पष्ट किया कि फ्रांस किसी युद्ध में सीधे शामिल नहीं है, बल्कि सहयोगियों के साथ क्षेत्र में शांति और संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।

तेहरान में इजराइली हमलों के बाद तेल भंडार ठिकानों में आग फैल गई, जिससे शहर की नालियों में आग की स्थिति बन गई। अमेरिका और इजराइल के हमलों से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है।

ईरान-इजरायल संघर्ष लंबा खिंचा तो दुबई में पड़ जाएंगे खाने-पीने के लाले

रियाद। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान तथा इजरायल के बीच जारी संघर्ष का असर अब खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था और आपूर्ति व्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। खासतौर पर दुबई में खाद्य आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। रिपोर्टों के अनुसार, शहर में ताजा फल और सब्जियों का भंडार सीमित रह गया है और यदि समुद्री व्यापार जल्द सामान्य नहीं हुआ तो स्थिति गंभीर हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुबई के पास ताजा खाद्य पदार्थों का केवल 8 से 10 दिन का स्टाक बचा था। बताया जा रहा है कि 7 मार्च तक यह भंडार घटकर करीब आठ दिनों का रह गया था। इसका मुख्य कारण स्ट्रैट आफ हार्मुज का बंद होना बताया जा रहा है, जो वैश्विक समुद्री व्यापार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। रिपोर्ट के अनुसार, विश्लेषक शनाका एंस्लेम परेरा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लाजिस्टिक्स विशेषज्ञ स्टीफन पाल के बयान का हवाला देते हुए कहा, कि सप्लाई चेन डेटा के आधार पर दुबई में खाद्य भंडार सीमित अवधि के लिए ही उपलब्ध है।

काठमांडू की हवा प्रदूषित,एक्यूआई 200 के पास

काठमांडू

नेपाल की राजधानी काठमांडू इस समय गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 200 के करीब पहुंच गया है। इस सूचकांक को बहुत अस्वस्थ की श्रेणी कहा जाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार हवा में मौजूद बेहद सूक्ष्म कण पीएम2.5 प्रदूषण का मुख्य कारण हैं। ये कण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं और खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से बीमार लोगों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं।

वातावरण विभाग के महानिदेशक ज्ञान राज सुवेदी ने बताया कि काठमांडू में खराब वायु गुणवत्ता के पीछे शहरी उत्सर्जन और प्रतिकूल मौसम की स्थिति दोनों जिम्मेदार हैं। शांत हवाएं और बारिश की कमी के कारण धुआं, धूल और अन्य प्रदूषक वातावरण में फैल नहीं पाते और घाटी में ही जमा हो जाते हैं।

उन्होंने कहा कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, विशेष रूप से डीजल चालित वाहन जो तय मानकों से अधिक धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण का बड़ा स्रोत बन गए हैं। इसके अलावा औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य से उठने वाली धूल, बायोमास जलाना और घरेलू ईंधन का उपयोग भी हवा को खराब कर रहे हैं।

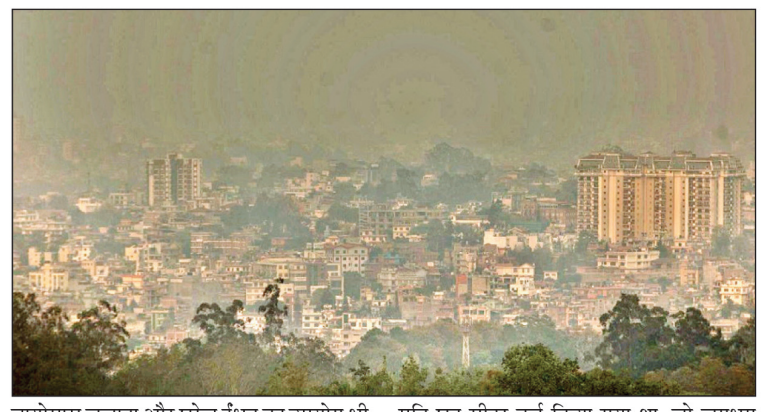

वातावरण विभाग का मानना है कि काठमांडू के आसपास के क्षेत्रों से आने वाला प्रदूषण और मौसमी जंगल की आग भी स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं। इसके अलावा तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण ऊर्जा खपत, परिवहन की मांग और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे पीएम2.5, कार्बन मोनोआक्साइड और नाइट्रोजन डाइआक्साइड जैसे प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि हो रही है।

आंकड़ों के अनुसार काठमांडू में प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है। वर्ष 2025 के आखिरी में शहर में पीएम2.5 का औसत स्तर 45.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया था, जो लगभग एक्यूआई 128 के बराबर है। यह स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय वार्षिक सुरक्षित सीमा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से लगभग नौ गुना अधिक है। वर्तमान में काठमांडू दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित प्रमुख शहरों में तीसरे स्थान पर है। पिछले 30 दिनों से काठमांडू की वायु गुणवत्ता लगातार अस्वस्थ श्रेणी में बनी हुई है।

विशेषज्ञों ने लोगों को विशेष रूप से प्रदूषण के चरम समय में बाहर कम निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम में बदलाव और उत्सर्जन नियंत्रण उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के बाद ही आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता में धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

नेपाल : 165 सांसदों में 40 वर्ष से कम आयु के 60 युवा सांसदों की जीत

काठमांडू

नेपाल में प्रतिनिधि सभा चुनाव के तहत सोमवार तक घोषित 160 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणामों के अनुसार नई संसद में 40 वर्ष से कम उम्र के सांसदों की संख्या 60 तक पहुंच गई है। हालांकि अभी 110 समानुपातिक सांसदों में भी कई युवा सांसदों के आने की उम्मीद है। नेपाल की कुल आबादी में 16 से 40 वर्ष आयु वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 40.35 प्रतिशत है। वर्ष 2022 के प्रतिनिधि सभा चुनाव में 165 निर्वाचन क्षेत्रों में से 40 वर्ष से कम उम्र के केवल 10 उम्मीदवार ही जीत पाए थे। उस समय 70 वर्ष से अधिक उम्र के 14 सांसद निर्वाचित हुए थे, जबकि 40 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सांसदों की संख्या सबसे अधिक (138) थी।

इस बार संसद में युवाओं की मजबूत मौजूदगी - हालांकि इस बार के चुनाव परिणामों ने संसद की उम्र संरचना में बड़ा परिवर्तन दिखाया है। अब तक घोषित परिणामों के अनुसार 40 वर्ष से कम उम्र के 60 उम्मीदवार प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं।इस वर्ग में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) का स्पष्ट वर्चस्व दिखाई दे रहा है। 60 में से 52 सांसद इसी पार्टी से चुने गए हैं, जबकि नेपाली से 4, सीपीएन यूएमएल से 2 और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी तथा श्रम संस्कृति पार्टी से एक-एक उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं।

25 वर्षीय प्रशांत सबसे युवा सांसद - मकवानपुर-2 से 25 वर्षीय प्रशांत उप्रेती इस बार के सबसे युवा प्रतिनिधि सभा सदस्य बने हैं। वो आरएसपी के तरफ से सांसद में निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा पूर्वी नवलपरासी-2 से 26 वर्षीय मनीष खनाल, कैलाली-2 से 26 वर्षीय केपी खनाल, रूपन्देही-2 से 28 वर्षीय सुलभ खरेल, सिरहा-1 से 28 वर्षीय बब्लु गुप्ता और झापा-1 से 29 वर्षीय निशा डांगी जैसे युवा नेता भी संसद में पहुंचे हैं। ये सभी आरएसपी से जीत कर आए हैं। इसी तरह काठमांडू-5 से 29 वर्षीय सस्मित पोखरेल, काठमांडू-1 से 30 वर्षीय रन्जु न्यौपाने, सिरहा-2 से 30 वर्षीय शिवशंकर यादव, चितवन-3 से 30 वर्षीय सोबिता गौतम, मोरंग-6 से 31 वर्षीय रुबिना आचार्य और प्युठान-1 से 31 वर्षीय सुशांत वैदिक भी आरएसपी से इसी युवा आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बालेन्द्र शाह भी युवा श्रेणी में - चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) भी भी युवा समूह में आते हैं। 36 वर्षीय शाह ने झापा-5 से के पी शर्मा ओली को पराजित कर प्रतिनिधि सभा की सीट जीती है।

मध्यम आयु वर्ग और वरिष्ठ नेताओं की स्थिति - 51 से 60 वर्ष आयु वर्ग के 36 उम्मीदवार प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित हुए हैं। इनमें से 28 रास्वपा से हैं, जबकि नेपाली कांग्रेस के 4 उम्मीदवार जीते हैं। इसके अलावा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और यूएमएल के दो-दो उम्मीदवार भी इसी आयु वर्ग में आते हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार अपेक्षाकृत कम संख्या में निर्वाचित हुए हैं। अब तक घोषित परिणामों के अनुसार इस आयु वर्ग के केवल 9 सांसद प्रतिनिधि सभा में पहुंचे हैं।

विश्लेषकों की राय - राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार संसद में युवाओं की बढ़ती भागीदारी उत्साहजनक संकेत है। हालांकि उनका कहना है कि यदि राजनीतिक शक्ति संतुलन नहीं बन पाया तो यह प्रभाव उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। राजनीतिक विश्लेषक सुचेता प्याकुरेल के अनुसार नेपाल की संसदीय राजनीति में युवाओं की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है। 1991 में युवा प्रतिनिधित्व 5 प्रतिशत से भी कम था, जो संविधान सभा काल में 8-10 प्रतिशत तक पहुंच गया और हाल के वर्षों में लगभग 12 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। वहीं युवा राजनीतिक विश्लेषक नवीन तिवारी का कहना है कि संसद में युवाओं की बढ़ती मौजूदगी सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन केवल उम्र के आधार पर बड़े बदलाव की उम्मीद करना सही नहीं होगा।